रोजगार के क्षेत्रवार वितरण का अध्ययन : छत्तीसगढ़ के संदर्भ में

Revati

Independent Scholar, (M.A. Sociology, SLET), Bilaspur, Chhattisgarh

सारांश

छत्तीसगढ़ में रोजगार का वितरण किन प्रमुख आयामों से प्रभावित होता है और यह राज्य की आर्थिक-सामाजिक संरचना को किस प्रकार प्रतिबिंबित करता है। रोजगार का स्वरूप केवल आर्थिक गतिविधियों तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह सामाजिक समावेशन, क्षेत्रीय संतुलन, लैंगिक समानता और विकास की दिशा से भी गहराई से जुड़ा होता है। अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि छत्तीसगढ़ की रोजगार संरचना में ग्रामीण क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है और आजीविका के अवसरों का बड़ा भाग अभी भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था से संबद्ध है। साथ ही, रोजगार व्यवस्था में लैंगिक असमानता भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जहाँ महिलाओं की भागीदारी पुरुषों की तुलना में कम है। विशेष रूप से नगरीय क्षेत्रों में यह असंतुलन अधिक स्पष्ट रूप में सामने आता है। दूसरी ओर, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएँ कृषि, पारिवारिक श्रम, मनरेगा तथा अन्य स्थानीय गतिविधियों में अपेक्षाकृत अधिक सक्रिय दिखाई देती हैं। इस प्रकार अध्ययन यह निष्कर्ष प्रस्तुत करता है कि छत्तीसगढ़ की रोजगार संरचना ग्रामीण प्रधान, पुरुष प्रधान तथा क्षेत्रीय और लैंगिक विषमताओं से प्रभावित है। अतः समावेशी और संतुलित विकास के लिए रोजगार के अवसरों का विस्तार, महिला सहभागिता में वृद्धि तथा रोजगार की गुणवत्ता में सुधार आवश्यक है।

परिचय

किसी भी राज्य की आर्थिक संरचना को समझने के लिए रोजगार का क्षेत्रवार वितरण एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण संकेतक माना जाता है। यह केवल इस बात को नहीं दर्शाता कि कितने लोग कार्यरत हैं, बल्कि यह भी बताता है कि कार्यरत जनसंख्या किन क्षेत्रों में केंद्रित है, रोजगार का स्वरूप कितना स्थिर या अस्थिर है, ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में रोजगार की प्रकृति कैसी है, तथा पुरुषों और महिलाओं की भागीदारी में कितना अंतर है। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में, जहाँ कृषि, वनों, खनन, लघु उद्योग, निर्माण, सेवाएँ तथा ग्रामीण रोजगार योजनाएँ समानांतर रूप से आर्थिक जीवन को प्रभावित करती हैं, वहाँ रोजगार के क्षेत्रवार वितरण का अध्ययन विशेष महत्व रखता है। राज्य के आधिकारिक सांख्यिकीय प्रकाशनों में श्रम एवं रोजगार से संबंधित अनेक संकेतक उपलब्ध हैं, जो इस विषय को तथ्यात्मक आधार प्रदान करते हैं। छत्तीसगढ़ के श्रम एवं रोजगार की आधारभूत स्थिति को देखें तो Chhattisgarh at a Glance 2024 के अनुसार जनगणना 2011 में राज्य की कुल कार्यरत जनसंख्या 12,180 हजार थी। इसमें मुख्य कार्यकर्ता 8,242 हजार तथा सीमांत कार्यकर्ता 3,938 हजार थे. इन आँकड़ों से स्पष्ट होता है कि राज्य में कार्यरत जनसंख्या का एक बड़ा भाग मुख्य कार्यकर्ताओं का है, किन्तु सीमांत कार्यकर्ताओं की संख्या भी कम नहीं है। यह तथ्य संकेत देता है कि छत्तीसगढ़ की रोजगार संरचना में एक ओर अपेक्षाकृत स्थिर रोजगार मौजूद है, तो दूसरी ओर अस्थिर, आंशिक अथवा मौसमी रोजगार का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए इस शोध में केवल कुल रोजगार का अध्ययन पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि रोजगार की प्रकृति और क्षेत्रीय संरचना का विश्लेषण भी आवश्यक होगा।

राज्य के रोजगार वितरण को ग्रामीण-नगरीय दृष्टि से देखने पर भी महत्वपूर्ण अंतर दिखाई देता है। आर्थिक गणना आधारित आँकड़ों के अनुसार राज्य में कुल कार्यरत व्यक्तियों की संख्या 18.61 लाख दर्ज की गई, जिनमें ग्रामीण क्षेत्र में 11.58 लाख तथा नगरीय क्षेत्र में 7.03 लाख कार्यरत व्यक्ति थे. इससे स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ में रोजगार का आधार अभी भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था से गहराई से जुड़ा हुआ है। यह स्थिति इस तथ्य की ओर संकेत करती है कि राज्य में प्राथमिक क्षेत्र, विशेषकर कृषि एवं उससे संबद्ध गतिविधियाँ, रोजगार के प्रमुख स्रोतों में से एक रही होंगी; जबकि नगरीय क्षेत्रों में उद्योग, व्यापार, सेवा और प्रशासनिक गतिविधियों का अपेक्षाकृत अधिक योगदान माना जा सकता है। अतः रोजगार के क्षेत्रवार वितरण का अध्ययन राज्य की ग्रामीण निर्भरता, नगरीय विस्तार और संरचनात्मक परिवर्तन को समझने का एक प्रभावी माध्यम बन जाता है। लैंगिक दृष्टि से भी रोजगार वितरण में उल्लेखनीय असमानता परिलक्षित होती है। उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार कुल कार्यरत व्यक्तियों में पुरुष 13.13 लाख तथा महिलाएँ 5.48 लाख थीं. ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी नगरीय क्षेत्र की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक दिखाई देती है, जबकि नगरीय रोजगार संरचना में पुरुष प्रधानता अधिक स्पष्ट है. यह तथ्य इस शोध को केवल क्षेत्रीय ही नहीं, बल्कि सामाजिक और लैंगिक आयामों से भी महत्त्वपूर्ण बनाता है। यदि किसी राज्य में रोजगार का वितरण क्षेत्रवार असंतुलित हो और उसमें लैंगिक असमानता भी जुड़ी हो, तो विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक समान रूप से नहीं पहुँच पाता। इसलिए छत्तीसगढ़ के संदर्भ में रोजगार का अध्ययन आर्थिक विकास, सामाजिक समावेशन और मानव संसाधन उपयोग– तीनों दृष्टियों से प्रासंगिक है।

छत्तीसगढ़ की रोजगार संरचना को समझने में ग्रामीण रोजगार योजनाओं के आँकड़े भी विशेष रूप से उपयोगी हैं। राज्य में मनरेगा के अंतर्गत 2023-24 में 38.60 लाख परिवार पंजीकृत थे, जबकि 27.60 लाख परिवारों ने रोजगार की मांग की, और इस योजना के माध्यम से 1,276.62 लाख मानव-दिवस रोजगार सृजित हुआ. यह दर्शाता है कि ग्रामीण क्षेत्र में सार्वजनिक रोजगार योजनाएँ आज भी आजीविका सुरक्षा का एक प्रमुख आधार हैं। साथ ही, 249,602 कार्य पूर्ण किए जाने का आँकड़ा यह इंगित करता है कि रोजगार सृजन केवल आय का साधन नहीं, बल्कि परिसंपत्ति निर्माण और ग्रामीण अवसंरचना विकास से भी जुड़ा हुआ है. अतः छत्तीसगढ़ के रोजगार का अध्ययन करते समय योजनाबद्ध सार्वजनिक रोजगार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, विशेषकर तब जब राज्य की बड़ी आबादी ग्रामीण अंचलों में निवास करती हो। इसी प्रकार, श्रम प्रशासन और रोजगार सेवाओं से संबंधित आँकड़े भी रोजगार व्यवस्था की संस्थागत पृष्ठभूमि को स्पष्ट करते हैं। राज्य के आधिकारिक प्रकाशनों में श्रम एवं रोजगार शीर्षक के अंतर्गत employment exchanges, labour courts, industrial courts तथा bonded labour rehabilitation जैसे संकेतकों का उल्लेख मिलता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि रोजगार का प्रश्न केवल उपलब्ध अवसरों तक सीमित नहीं है, बल्कि वह पंजीयन, नियोजन, विवाद निपटान तथा श्रमिक संरक्षण जैसी संस्थागत व्यवस्थाओं से भी जुड़ा हुआ है. इसलिए इस अध्ययन में रोजगार को केवल आर्थिक चर के रूप में नहीं, बल्कि प्रशासनिक, सामाजिक और विकासात्मक संदर्भों में भी देखा जाना आवश्यक है। यह दृष्टिकोण शोध को अधिक यथार्थवादी और नीति-उन्मुख बनाता है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में रोजगार का वितरण बहुआयामी है, जिसमें मुख्य एवं सीमांत कार्य, ग्रामीण एवं नगरीय विभाजन, लैंगिक भागीदारी, सार्वजनिक रोजगार योजनाएँ और संस्थागत रोजगार तंत्र–सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यद्यपि उपलब्ध आँकड़ों में कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों के अनुसार नवीनतम प्रत्यक्ष वर्गीकरण सीमित रूप में प्राप्त होता है, फिर भी आधिकारिक प्रकाशनों में उपलब्ध श्रम, आर्थिक गणना, ग्रामीण रोजगार और सामाजिक-आर्थिक संकेतकों के आधार पर राज्य की रोजगार संरचना की दिशा, प्रवृत्ति और असंतुलन का समुचित विश्लेषण किया जा सकता है. इस प्रकार प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य छत्तीसगढ़ में रोजगार के क्षेत्रवार वितरण का विश्लेषण करना, विभिन्न श्रेणियों में रोजगार की प्रकृति को समझना, तथा राज्य की रोजगार संरचना में निहित चुनौतियों और संभावनाओं को रेखांकित करना है।

साहित्य समीक्षा

रोजगार के क्षेत्रवार वितरण का अध्ययन विकास अर्थशास्त्र का एक महत्त्वपूर्ण विषय रहा है, क्योंकि किसी भी अर्थव्यवस्था में श्रम का प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों के बीच स्थानांतरण आर्थिक संरचनात्मक परिवर्तन का प्रमुख संकेतक माना जाता है। इस संदर्भ में Bosworth, Collins और Virmani (2007) ने भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि प्रक्रिया का विश्लेषण करते हुए बताया कि भारत में उत्पादन संरचना में बदलाव तो हुआ, परंतु रोजगार का स्थानांतरण उतनी तीव्र गति से नहीं हुआ। उनके अनुसार सेवा क्षेत्र का विस्तार तेज रहा, लेकिन उसमें उच्च-कौशल आधारित रोजगार की प्रधानता ने व्यापक श्रम-शक्ति को समान रूप से absorb नहीं किया. भारतीय रोजगार संरचना के दीर्घकालीन परिवर्तन को समझने में Papola और Sahu (2012) का कार्य विशेष रूप से उल्लेखनीय माना जाता है। उन्होंने यह रेखांकित किया कि भारत में रोजगार संरचना में परिवर्तन हुआ है, परंतु यह परिवर्तन असमान और धीमा रहा। कृषि से श्रम का निर्गमन हुआ, लेकिन उद्योग क्षेत्र उतनी मात्रा में रोजगार सृजित नहीं कर सका, जितनी अपेक्षा थी। फलतः सेवा क्षेत्र ने रोजगार अवशोषण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई, परंतु वहाँ भी रोजगार की गुणवत्ता और स्थायित्व एक चुनौती बने रहे। इसी बहस को आगे बढ़ाते हुए Kannan और Raveendran (2009) ने "growth sans employment" की अवधारणा के माध्यम से यह दिखाया कि विशेषकर संगठित विनिर्माण क्षेत्र में उत्पादन वृद्धि के बावजूद रोजगार वृद्धि कमजोर रही। उनके अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि केवल आर्थिक वृद्धि अपने आप पर्याप्त रोजगार सृजित नहीं करती; इसके लिए क्षेत्रीय संरचना, तकनीक, श्रम-गहनता और नीति-समर्थन जैसे कारक भी निर्णायक होते हैं. भारतीय रोजगार प्रवृत्तियों की पुनर्समीक्षा करते हुए Himanshu (2011) ने यह बताया कि भारत में रोजगार के आँकड़ों की सतही व्याख्या कई बार भ्रामक हो सकती है, क्योंकि कुल रोजगार वृद्धि के पीछे कार्य के प्रकार, श्रम भागीदारी, अनौपचारिकता और क्षेत्रीय विषमता जैसे तत्व छिपे रहते हैं। उनका अध्ययन इस बात पर बल देता है कि रोजगार का अध्ययन केवल कुल संख्या के आधार पर नहीं, बल्कि उसकी संरचना, गुणवत्ता और श्रेणीगत वितरण के आधार पर किया जाना चाहिए। भारतीय अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन और उत्पादक रोजगार के संबंध का विश्लेषण करते हुए Basole (2022) ने कहा कि सतत आय-वृद्धि और बेहतर रोजगार परिस्थितियों के लिए केवल कृषि से श्रम का बाहर जाना पर्याप्त नहीं है; आवश्यक यह है कि श्रम उच्च उत्पादकता वाले गैर-कृषि क्षेत्रों में स्थानांतरित हो। उनके अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि भारत में यह परिवर्तन आंशिक रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रमिक आज भी निम्न-उत्पादकता और अनौपचारिक गतिविधियों में लगे हुए हैं। रोजगार संरचना के व्यापक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में ILO और Institute for Human Development (2024) की India Employment Report 2024 अत्यंत उपयोगी है। इस रिपोर्ट में युवाओं, महिलाओं, शिक्षा, कौशल और रोजगार की बदलती प्रकृति पर प्रकाश डाला गया है। रिपोर्ट बताती है कि भारत में रोजगार की समस्या केवल बेरोजगारी तक सीमित नहीं है, बल्कि underemployment, informal employment, और low-productivity employment भी बड़े मुद्दे हैं। यह निष्कर्ष छत्तीसगढ़ जैसे राज्य के संदर्भ में विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण हो जाता है, जहाँ ग्रामीण और असंगठित रोजगार का हिस्सा अपेक्षाकृत अधिक है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार के परिवर्तन को लेकर NITI Aayog (2017) ने यह रेखांकित किया कि ग्रामीण भारत में रोजगार का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। कृषि पर निर्भरता धीरे-धीरे कम हो रही है, परंतु इसके स्थान पर जो गैर-कृषि रोजगार उभर रहा है, वह अधिकतर निर्माण, लघु सेवाओं और कम वेतन वाले कार्यों में केंद्रित है। इसी प्रकार ILO (2018) और ILO (2016) के भारत संबंधी श्रम बाजार अध्ययनों में यह स्पष्ट किया गया है कि भारत में संरचनात्मक परिवर्तन के बावजूद श्रम का बड़ा भाग अभी भी अनौपचारिक, असुरक्षित और निम्न-उत्पादकता वाले कार्यों में संलग्न है। इन अध्ययनों में यह भी बल दिया गया है कि कृषि से श्रम का बहिर्गमन तभी सार्थक माना जाएगा जब उद्योग और सेवाओं में पर्याप्त, सम्मानजनक और नियमित रोजगार उपलब्ध हों।

सांख्यिकीय विश्लेषण

संकेतक	मान (लाख)	संकेतक	मान (%)
कुल कार्यरत व्यक्ति	18.61	ग्रामीण हिस्सेदारी	62.22
ग्रामीण कार्यरत व्यक्ति	11.58	नगरीय हिस्सेदारी	37.78
नगरीय कार्यरत व्यक्ति	7.03	पुरुष हिस्सेदारी	70.55
ग्रामीण पुरुष	7.44	महिला हिस्सेदारी	29.45
ग्रामीण महिला	4.14	ग्रामीण पुरुष प्रतिशत	64.25
ग्रामीण कुल	11.58	ग्रामीण महिला प्रतिशत	35.75
नगरीय पुरुष	5.69	नगरीय पुरुष प्रतिशत	80.94
नगरीय महिला	1.34	नगरीय महिला प्रतिशत	19.06
नगरीय कुल	7.03		
पुरुष कार्यरत व्यक्ति	13.13		
महिला कार्यरत व्यक्ति	5.48		

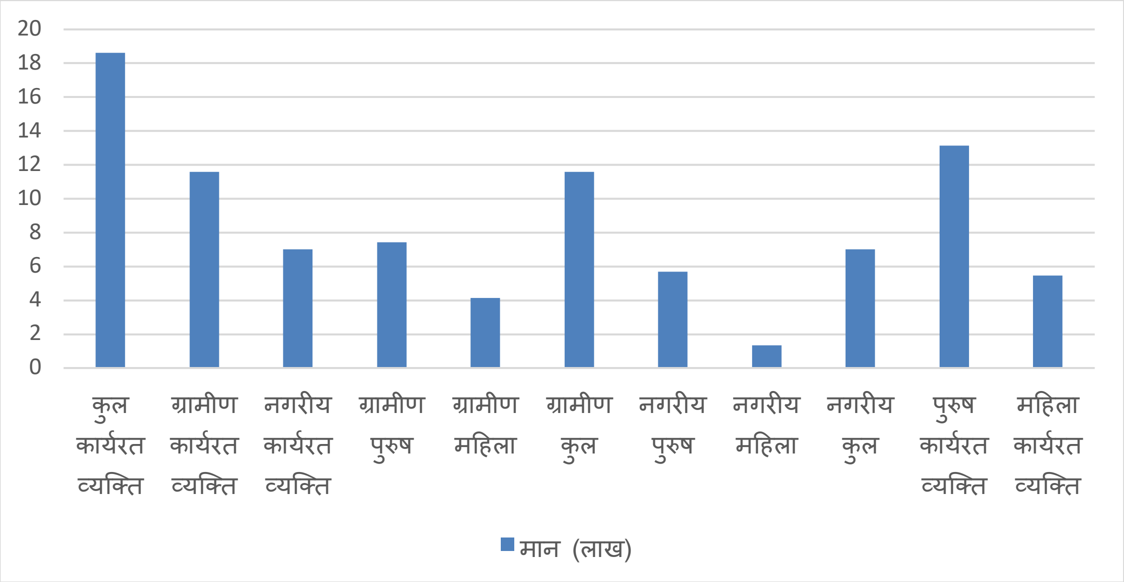

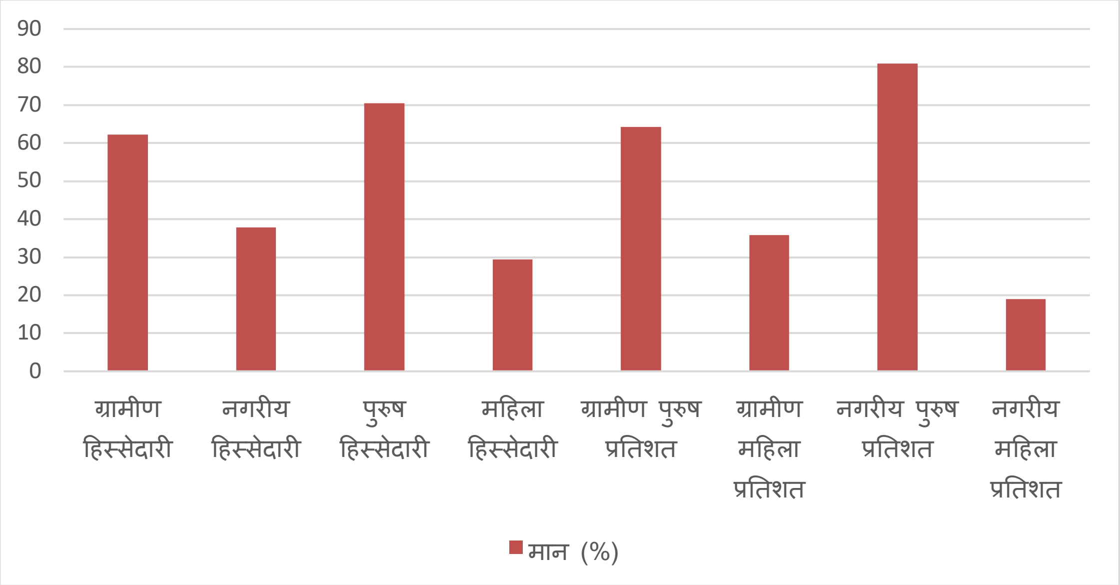

नीचे दिए गए आँकड़ों की व्याख्या से छत्तीसगढ़ में रोजगार के वितरण की एक स्पष्ट संरचना सामने आती है। सबसे पहले, कुल 18.61 लाख कार्यरत व्यक्तियों में से 11.58 लाख ग्रामीण और 7.03 लाख नगरीय क्षेत्र में कार्यरत हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि राज्य में रोजगार का आधार मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्र पर टिका हुआ है। ग्रामीण हिस्सेदारी 62.22 प्रतिशत तथा नगरीय हिस्सेदारी 37.78 प्रतिशत होने का अर्थ है कि छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में आज भी ग्रामीण आजीविका, कृषि-संबद्ध गतिविधियाँ, लघु कार्य, असंगठित श्रम तथा स्थानीय रोजगार के अवसर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह स्थिति राज्य की आर्थिक संरचना में ग्रामीण प्रधानता को दर्शाती है। लैंगिक दृष्टि से देखें तो कुल कार्यरत व्यक्तियों में पुरुष 13.13 लाख और महिलाएँ 5.48 लाख हैं। अर्थात पुरुष हिस्सेदारी 70.55 प्रतिशत और महिला हिस्सेदारी 29.45 प्रतिशत है। यह स्पष्ट रूप से बताता है कि रोजगार में पुरुषों की भागीदारी महिलाओं की तुलना में काफी अधिक है। यह अंतर केवल श्रम बाजार की असमानता को नहीं दर्शाता, बल्कि सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक और अवसरगत सीमाओं की ओर भी संकेत करता है, जिनके कारण महिलाएँ रोजगार में अपेक्षित स्तर तक शामिल नहीं हो पातीं। इसलिए यह कहा जा सकता है कि राज्य में रोजगार संरचना अभी भी लैंगिक रूप से संतुलित नहीं है।

ग्रामीण क्षेत्र के भीतर भी पुरुष और महिला सहभागिता में अंतर दिखाई देता है। ग्रामीण कुल 11.58 लाख कार्यरत व्यक्तियों में 7.44 लाख पुरुष और 4.14 लाख महिलाएँ हैं। प्रतिशत के रूप में देखें तो ग्रामीण पुरुष 64.25 प्रतिशत और ग्रामीण महिला 35.75 प्रतिशत हैं। इसका अर्थ यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी नगरीय क्षेत्र की तुलना में अपेक्षाकृत बेहतर है। यह स्थिति इस बात की ओर संकेत करती है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाएँ कृषि, पशुपालन, वनोपज संग्रह, घरेलू उद्योगों, मनरेगा तथा पारिवारिक श्रम जैसी गतिविधियों में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। फिर भी उनका अनुपात पुरुषों से कम है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि ग्रामीण क्षेत्र में भी पूर्ण लैंगिक समानता नहीं है।

नगरीय क्षेत्र में यह असमानता और अधिक स्पष्ट हो जाती है। नगरीय कुल 7.03 लाख कार्यरत व्यक्तियों में 5.69 लाख पुरुष तथा केवल 1.34 लाख महिलाएँ हैं। इससे नगरीय पुरुष प्रतिशत 80.94 तथा नगरीय महिला प्रतिशत 19.06 निकलता है। यह बहुत महत्वपूर्ण निष्कर्ष है, क्योंकि यह बताता है कि शहरी रोजगार में महिलाओं की भागीदारी अत्यंत सीमित है। इसका कारण कौशल, शिक्षा, सुरक्षित कार्यस्थल, सामाजिक मान्यताएँ, घरेलू दायित्व, तथा औपचारिक क्षेत्र में सीमित पहुँच जैसे कारक हो सकते हैं। इस प्रकार नगरीय रोजगार संरचना पुरुष प्रधान दिखाई देती है। इन आँकड़ों का समेकित अर्थ यह है कि छत्तीसगढ़ में रोजगार वितरण तीन प्रमुख विशेषताओं से चिह्नित है—ग्रामीण प्रधानता, पुरुष प्रधानता, और नगरीय क्षेत्रों में महिलाओं की बहुत कम भागीदारी। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर अपेक्षाकृत अधिक हैं, परंतु वे संभवतः निम्न आय, असंगठित और पारंपरिक गतिविधियों से जुड़े हो सकते हैं। दूसरी ओर, नगरीय क्षेत्रों में रोजगार का स्वरूप अपेक्षाकृत संगठित और विविधतापूर्ण हो सकता है, लेकिन वहाँ महिलाओं की भागीदारी काफी कम है। इसलिए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि राज्य में रोजगार का वितरण केवल क्षेत्रीय असमानता ही नहीं, बल्कि लैंगिक असंतुलन को भी प्रतिबिंबित करता है।

निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन से यह स्पष्ट रूप से सामने आता है कि छत्तीसगढ़ की रोजगार संरचना बहुआयामी होने के बावजूद मुख्यतः ग्रामीण और पुरुष-प्रधान स्वरूप की है। कुल कार्यरत व्यक्तियों में ग्रामीण हिस्सेदारी का अधिक होना इस बात का संकेत है कि राज्य की अर्थव्यवस्था अब भी बड़ी मात्रा में कृषि, कृषि-संबद्ध गतिविधियों, ग्रामीण असंगठित श्रम तथा स्थानीय आजीविका पर आधारित है। यह स्थिति एक ओर ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिक भूमिका को रेखांकित करती है, तो दूसरी ओर यह भी बताती है कि राज्य में संरचनात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया अभी पूर्णतः संतुलित नहीं हुई है। नगरीय क्षेत्रों में रोजगार के अवसर अपेक्षाकृत कम

व्यक्तियों तक सीमित दिखाई देते हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उद्योग, व्यापार और आधुनिक सेवाओं का विस्तार अभी भी श्रम के व्यापक अवशोषण की दृष्टि से पर्याप्त नहीं है।

लैंगिक विश्लेषण इस अध्ययन का एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष प्रस्तुत करता है। कुल रोजगार में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों की तुलना में काफी कम है, और नगरीय क्षेत्रों में यह असमानता और अधिक तीव्र रूप में दिखाई देती है। इससे स्पष्ट होता है कि रोजगार का प्रश्न केवल अवसरों की उपलब्धता तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा, कौशल, सामाजिक संरचना, सुरक्षा, पारिवारिक दायित्व और औपचारिक क्षेत्र तक पहुँच जैसे कारक भी इससे गहराई से जुड़े हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की अपेक्षाकृत बेहतर भागीदारी यह दर्शाती है कि वे राज्य की उत्पादन प्रक्रिया का महत्त्वपूर्ण हिस्सा हैं, किन्तु उनके कार्य का बड़ा भाग संभवतः असंगठित, कम आय वाला या अदृश्य श्रम की श्रेणी में आता है। इसलिए समावेशी विकास के लिए आवश्यक है कि महिला रोजगार को औपचारिक मान्यता, कौशल विकास, सुरक्षित कार्य-परिसर और संस्थागत समर्थन मिले। अंततः कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में रोजगार का वितरण केवल क्षेत्रीय अंतर का विषय नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और संरचनात्मक असंतुलनों का भी दर्पण है। राज्य में रोजगार के संतुलित विकास हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादक रोजगार के अवसर बढ़ाना, गैर-कृषि गतिविधियों का विस्तार करना, नगरीय क्षेत्रों में महिला रोजगार भागीदारी को प्रोत्साहित करना तथा रोजगार की गुणवत्ता और स्थायित्व पर बल देना आवश्यक है। इस अध्ययन से यह भी संकेत मिलता है कि भविष्य में कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों के प्रत्यक्ष वर्गीकरण के आधार पर अधिक विस्तृत शोध की आवश्यकता है, ताकि रोजगार के वास्तविक क्षेत्रीय स्वरूप को और गहराई से समझा जा सके। इस प्रकार यह अध्ययन न केवल छत्तीसगढ़ की वर्तमान रोजगार स्थिति को स्पष्ट करता है, बल्कि नीति-निर्माण के लिए भी उपयोगी दिशा प्रदान करता है।

संदर्भ सूची

1. Basole, A. (2022). Structural transformation and employment generation in India: Past performance and the way forward. Indian Journal of Labour Economics, 65(2), 437–457. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9288666/
2. Bosworth, B., Collins, S. M., & Virmani, A. (2007). Sources of growth in the Indian economy (NBER Working Paper No. 12901). National Bureau of Economic Research. https://www.nber.org/system/files/working_papers/w12901/w12901.pdf
3. International Labour Organization, & Institute for Human Development. (2024). India employment report 2024: Youth employment, education and skills. International Labour Organization. https://www.ilo.org/sites/default/files/2024-08/India%20Employment%20-%20web_8%20April.pdf
4. Kannan, K. P., & Raveendran, G. (2009). Growth sans employment: A quarter century of jobless growth in India's organised manufacturing. Economic and Political Weekly, 44(10), 80–91. https://www.epw.in/journal/2009/10/special-articles/growth-sans-employment-quarter-century-jobless-growth-indias
5. Papola, T. S., & Sahu, P. P. (2012). Growth and structure of employment in India: Long-term and post-reform performance and the emerging challenge. Institute for Studies in Industrial Development. http://isidev.nic.in/pdf/ICSSR_TSP_PPS.pdf
6. Sahu, R. K. (2021). Role of MGNREGA in rural livelihood security in Chhattisgarh. International Journal of Research and Analytical Reviews, 8(2). https://www.ijrar.org/papers/IJRAR21BXXXX.pdf
7. Ghose, A. K. (2020). *Employment in India*. Oxford University Press.
8. Jha, P. (2016). *Labour in contemporary India*. Oxford University Press.

9. Sen, A. (1999). *Employment, technology and development*. Oxford University Press.
10. Directorate of Economics and Statistics, Chhattisgarh. (2024). *Chhattisgarh at a glance 2024*. Government of Chhattisgarh. https://descg.gov.in/pdf/publications/latest/Chhattisgarh_at_Glance_2024.pdf
11. Directorate of Economics and Statistics, Chhattisgarh. (n.d.). *Publication page*. Government of Chhattisgarh. https://descg.gov.in/Publication.aspx
12. Directorate of Economics and Statistics, Chhattisgarh. (2012–13). *Economic survey of Chhattisgarh*. Government of Chhattisgarh. https://descg.gov.in/pdf/publications/allpub/3.EconomicSurvey2012-13%28English%29.pdf
13. Directorate of Economics and Statistics, Chhattisgarh. (n.d.). *Economic survey*. Government of Chhattisgarh. https://descg.gov.in/Economic-Survey.aspx
14. Government of India, NITI Aayog. (2017). *Changing structure of rural economy of India: Implications for employment and growth*. https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2021-008/11_Rural_Economy_Discussion_Paper_0.pdf